झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 3309/2023

पंकज कुमार दास, उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र वीरेंद्र कुमार राम, निवासी ग्राम- आसना इंद्रवा,डाकघर- झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा (झारखंड)

....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री साहिल, अधिवक्ता,
श्री शशि कांत मिश्रा, अधिवक्ता
श्री अविनाश कुमार, अधिवक्ता
श्री सचिन महतो, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री शिवशंकर कुमार, अतिरिक्त लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर किया गया है, जिसमें बरही थाना में दर्ज केस संख्या 261/2023 के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 09.08.2023 को जी.आर. संख्या 1403/2023 में संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द

करने का अनुरोध किया गया है जिसे सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध करने पर सत्र विचरण संख्या 458/2023 के रूप में पंजीकृत हुआ है। जिसके द्वारा और जहां नीचे दी गई अदालत के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 364 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया गया है; और यह केस अब गया है और उक्त मामला अब अदालत में लंबित है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हजारीबाग की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता प्रथम सचना रिपोर्ट को दिनांक 06.06.2023 दर्ज करने से पांच साल पहले सूचक का यौन शोषण कर रहा था। दिनांक; उससे शादी करने के बहाने। याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप है कि दिनांक 02.05.2023 को, याचिकाकर्ता ने झुमरी तिलैया के एक होटल में सूचक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। दिनांक 04.06.2023 को याचिकाकर्ता ने सूचना देने वाले को बरही बुलाया और सूचना देने वाले को बाइक से जंगल की ओर ले गया जहां सूचना देने वाले ने याचिकाकर्ता के तीन दोस्तों को देखा। सूचक के मन में संदेह पैदा हुआ कि याचिकाकर्ता उसे मार सकता है। सूचक ने याचिकाकर्ता को बाइक रोकने का निर्देश दिया लेकिन याचिकाकर्ता ने बाइक रोकने के बजाय बाइक की गति बढ़ा दी। सूचना देने वाले ने शोर मचा दिया। कई लोग वहां जमा हो गए और याचिकाकर्ता और उसके दोस्त भाग गए। बाइक को पुलिस को सौंप दिया गया। मामले की जांच के बाद, पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को सही पाया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 09.08.2023 के आदेश के अनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, हजारीबाग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठे हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का कोई इरादा किए बिना सूचक से शादी करने का वादा किया था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुलग्नक-2 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक स्पष्ट दस्तावेज है, जिसमें याचिकाकर्ता कर्मचारी है और जो यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता को 08.05.2023 को

पूर्वाह्न और दोनों तारीखों को 02.05.2023 और 04.05.2023 को छुट्टी दी गई थी, इस मामले की घटना की कथित तिथि पर, याचिकाकर्ता जम्मू और कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में था। अनुलग्नक-3 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, जो याचिकाकर्ता का रेलवे यात्रा टिकट है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जम्मू तवी से 08 मई, 2023 को 20:30 बजे कोलकाता एक्सप्रेस में सवार हुआ और 10 मई, 2023 को 7:46 बजे कोडरमा जंक्शन पहुंचा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 04.06.2023 को हजारीबाग जिले में स्थित घटना के कथित स्थान पर याचिकाकर्ता की उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है।

6. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले भी सूचना देने वाले ने याचिकाकर्ता के खिलाफ स्व-आरोप लगाते हुए 2019 का शिकायत मामला संख्या 508 दायर किया था और इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अनुलग्नक-5 की ओर इस अदालत का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि 2019 के उक्त शिकायत मामले संख्या 508 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा पारित फैसले की प्रमाणित प्रति की प्रति है; जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी एक संजीत कुमार दास से हुई थी और संजीत कुमार दास के साथ शादी के बाद भी वह याचिकाकर्ता से बात करती थी। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होता था। इसलिए, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने सूचक से कहा कि उसके पति के साथ तलाक के बाद, वे याचिकाकर्ता के साथ उसकी शादी कराएंगे और शादी की तारीख भी तय की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपने पति को तलाक दे दिया लेकिन जब सूचक ने याचिकाकर्ता के साथ शादी के लिए जोर दिया, तो याचिकाकर्ता ने मांग की,शिकायतकर्ता ने दहेज की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शादी करने से इनकार कर दिया और 26.03.2019 को, याचिकाकर्ता ने सूचना देने वाले के साथ अवैध संबंध स्थापित किए। उस मामले में मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता ने कोई गवाह या तो मौखिक या दस्तावेजी पेश नहीं किया और मामला को बिना किसी साक्ष्य के बंद कर दिया गया और याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी नहीं पाया गया और इन सभी तथ्यों को सूचना देने वाले द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए दबा दिया गया है और वही राशि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बरही थाना केस संख्या 261/2023 के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 09.08.2023 को

संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया जो जी.आर. संख्या 1403/2023 के अनुरूप का मामला है, जिसके द्वारा और जहां नीचे दी गई अदालत के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उक्त बरही थाना की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया गया है, जो अब विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, हजारीबाग की अदालत में लंबित है, को खारिज कर दिया जाए और याचिकाकर्ता के विरुद्ध अलग रख दिया जाए।

7. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने बरही थाना केस संख्या 261/2023 के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 09.08.2023 को संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया गया जो जी.आर. संख्या 1403/2023 के अनुरूप का मामला है, जिसके द्वारा और जहां नीचे दी गई अदालत के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 364 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उक्त बरही थाना की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया गया है, जो अब विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, हजारीबाग की अदालत में लंबित है, जो अब विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1, हजारीबाग की अदालत में लंबित है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शादी के झूठे बहाने से सूचना देने वाले के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है।, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका संख्या में कोई योग्यता नहीं है, और उस को खारिज कर दिया जाए।

8. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृष्ण लाल चावला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में और (2021) 5 एससीसी 435 अनुच्छेद -13 और 26 में रिपोर्ट किया गया है, जिनमें से निम्नलिखित हैं:

13. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी 2 ने अपने द्वारा स्थापित नए शिकायत मामले में जानबूझकर इस तथ्य को दबाया है कि उसी घटना के संबंध में उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही एक आरोप पत्र दायर किया गया था। जो गैर संज्ञेय रिपोर्ट संख्या

160/2017 (अपराध संख्या 283/2017) अपीलार्थी 1 के पुत्र द्वारा दायर किया गया। इस आरोप-पत्र का कोई संदर्भ निजी शिकायत में या प्रतिवादी 2 और उसकी पत्नी द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दिए गए बयानों में नहीं मिलता है। वास्तव में, उनकी पत्नी की ओर से दायर निजी शिकायत और बयान दोनों में केवल यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि उनकी एनसीआर संख्या 158/2012 के अनुसार जांच चल रही है। पत्नी के बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करना वादी का परम कर्तव्य है। यह तुच्छ कानून का मामला है, और फिर भी दोहराया जाता है, कि अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों का दमन अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर है, और एक भारी हाथ से निपटा जाएगा (राम धन बनाम यू.पी. राज्य। [राम धन बनाम यू. पी राज्य, (2012) 5 एससीसी 536: (2012) 3 एससीसी (सीआरआई) 237]; के. डी. शर्मा बनाम सेल [के.डी.] शर्मा बनाम सेल, (2008) 12 एससीसी 481])

26. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि इस न्यायालय के पास अपनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्तियां हैं, कि यह न्यायालय न्याय की संस्था का अनुचित साधनों के लिए उपयोग करने वाले वादी को पीड़ित नहीं करेगा। इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह एक वादी को किसी भी राहत से इनकार करे जो अपने अशुद्ध हाथों से न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है। इसी तरह, तुच्छ और परेशान करने वाली कार्यवाही का पीछा करने वाला वादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदालत के समय और सार्वजनिक धन पर असीमित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। (जोर दिया गया है) कि तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करना वादी का बाध्य कर्तव्य है। यह एक तुच्छ कानून का मामला है कि अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों का दमन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

9. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोनू @सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में और (2021) 18 एससीसी 517 में एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थापित करने के लिए कि क्या कथित बलात्कार के मामले में "सहमति" शादी के वादे से उत्पन्न होने वाली "तथ्य की गलत धारणा" से दूषित है, दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। विवाह का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो गलत विश्वास में दिया गया था और जिस समय इसे दिया गया था उस समय इसका पालन करने का

कोई इरादा नहीं था और वादा अपने आप में तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, या यौन कृत्य में शामिल होने के महिला के फैसले के साथ सीधा संबंध होना चाहिए।

10. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2020) 10 एस. सी. सी. 108 में में रिपोर्ट किए गए महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य के मामले में अनुच्छेद संख्या 14, 15 और 20 में अभिनिर्धारित किया है

"14. आई.पी.सी. की धारा 90 के तहत, तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है। लेकिन तथ्य की गलत धारणा घटना के समय की निकटता में होनी चाहिए और चार साल की अवधि में नहीं फैल सकती है। इसे शायद ही किसी विस्तार की आवश्यकता है कि अपीलार्थी द्वारा सहमति उचित विचार-विमर्श के बाद उसके द्वारा किया गया एक सचेत और सूचित विकल्प था, यह विरोध न करने के लिए एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई के साथ लंबे समय तक फैला हुआ था। अभियोजक ने अपीलार्थी को लिखे अपने पत्रों में यह भी उल्लेख किया है कि रिश्ते के संबंध में उसके घर पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर झगड़े होते थे और उसे पीटा जाता था।

15. उदय [उदय बनाम कर्नाटक राज्य, (2003) 4 एस. सी. सी. 46:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 775] के मामले में, अपीलार्थी और अभियोक्त्री एक ही पड़ोस में रहते थे। चूंकि वे अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए विवाह की समझ और आश्वासन पर उनके बीच शारीरिक संबंध बने रहने के बावजूद वैवाहिक संबंध फलीभूत नहीं हो सके। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एससीसी, पृष्ठ 56-57, अनुच्छेद 21)

"21. अतः ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक राय की सर्वसम्मति इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि अभियोजक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए दी गई सहमति, जिससे वह इस वादे पर गहरा प्रेम करती है कि वह बाद की तारीख में उससे शादी करेगा, को तथ्य की गलत धारणा के तहत नहीं कहा जा सकता है। एक झूठा वादा संहिता के अर्थ के भीतर एक तथ्य नहीं है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हमें यह जोड़ना होगा कि यह निर्धारित करने के लिए कोई सार्वभौमिकता सूत्र नहीं है कि क्या अभियोजक द्वारा यौन संभोग के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है, या क्या यह तथ्य की गलत धारणा एक के तहत

दी गई है। अंतिम विश्लेषण में, अदालतों द्वारा निर्धारित परीक्षण सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायिक दिमाग को सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन अदालत को, प्रत्येक मामले में, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अपने सामने के साक्ष्य और आसपास की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य हैं जो इस सवाल पर असर डाल सकते हैं कि क्या सहमति स्वैच्छिक थी, या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई थी। इसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सबूतों का वजन भी करना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक घटक को साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, सहमति का अभाव उनमें से एक है।

20. हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजक की सहमति एक सचेत और जानबूझकर किया गया विकल्प था, जो एक अनैच्छिक कार्रवाई या इनकार से अलग था और उसके लिए कौन सा अवसर उपलब्ध था, क्योंकि अपीलार्थी के लिए उसके गहरे प्रेम के कारण वह स्वेच्छा से उसे अपने शरीर के साथ स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए प्रेरित करती थी, जो सामान्य मानव व्यवहार के अनुसार केवल उस व्यक्ति को अनुमति दी जाती है जिसके साथ वह गहरा प्यार करता है। उदय [उदय बनाम कर्नाटक राज्य, (2003) 4 एस.सी.सी. 46:2003 एस.सी.सी. (सी.आर. ई.) 775] में इस संबंध में टिप्पणियों को प्रासंगिक माना जाता हैः (एससी सी, पृष्ठ, 58, अनुच्छेद 25)

25. . जैसा कि अभियोजक ने कहा है कि अपीलार्थी ने भी एक से अधिक अवसरों पर ऐसा वादा किया था। ऐसी परिस्थितियों में वादा सभी महत्व खो देता है, विशेष रूप से जब वे भावनाओं और जुनून से उबर जाते हैं और खुद को ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में पाते हैं जहां वे एक कमजोर क्षण में यौन संबंध बनाने के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था, और अभियोजक ने स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ संभोग करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे वह गहरा प्यार करती थी, इसलिए नहीं कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था, बल्कि इसलिए कि वह भी उससे शादी करना चाहती थी। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी के ज्ञान पर यह आरोप लगाना बहुत कठिन होगा कि अभियोजक ने अपने वादे से उत्पन्न तथ्य की गलत धारणा के परिणामस्वरूप सहमति दी थी। किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी के लिए यह जानना संभव नहीं था कि जब उसने सहमति दी तो अभियोजक के मन में क्या था, क्योंकि उसके लिए सहमति देने के लिए एक से अधिक कारण

थे। (जोर दिया गया) और कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि तथ्य की गलत धारणा घटना के समय के निकट होनी चाहिए और इसे चार साल की अवधि में नहीं फैलाया जा सकता है।

11. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ बिल्कुल कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का कभी भी सूचक से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। सूचना देने वाले का कथित यौन शोषण पांच वर्षों की अवधि में किया गया और जिसके बीच सूचना देने वाले ने 2019 में का शिकायत मामला संख्या 508 भी स्थापित किया, लेकिन उस मामले के लंबित होने के दौरान, जिसका मुकदमा केवल 25.05.2023 को समाप्त हुआ था; सूचना देने वाला याचिकाकर्ता को शादी के झूठे बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकता था जब उक्त शिकायत का मामला बहुत अधिक लंबित था। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों से, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ इसी तरह के आरोपों पर मामले की पिछली संस्था के भौतिक तथ्यों को दबाकर प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए स्थापित एक झूठा मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया है, इसलिए, इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होगा।

12. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है की बरही थाना में दर्ज केस संख्या 261/2023 के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 09.08.2023 को जी.आर. संख्या 1403/2023 में संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसे सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध करने पर सत्र विचरण संख्या 458/2023 के रूप में पंजीकृत हुआ है। जिसके द्वारा और जहां नीचे दी गई अदालत के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 364 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया गया है; और यह केस अब गया है और उक्त मामला अब अदालत में लंबित है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हजारीबाग की अदालत में लंबित है, को खारिज कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया जाए।

13. तदनुसार, बरही थाना में दर्ज केस संख्या 261/2023 के संबंध में विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा दिनांक 09.08.2023 को जी.आर. संख्या 1403/2023 में संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसे सत्र न्यायालय में

प्रतिबद्ध करने पर सत्र विचरण संख्या 458/2023 के रूप में पंजीकृत हुआ है। जिसके द्वारा और जहां नीचे दी गई अदालत के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 364 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया गया है; और यह केस अब गया है और उक्त मामला अब अदालत में लंबित है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हजारीबाग की अदालत में लंबित है को खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता पदच्युत कर दिया जाता है

14. नतीजतन, इस विविध आपराधिक याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी,न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 12 फरवरी, 2024

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिये द्वारा किया गया है।